Since the Government have decided to give house sites to the rural poor, it should move immediately in the matter and see that the Chakdeo villagers do not have to suffer any more.

(ii) Need for a Committee to consider the problems arising out of the closure of brick kilns

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति जी, देश में ईंट निर्माताओं ने उत्पादन करना बन्द कर दिया है। गत वर्षों में निर्मित किया गया ईंट बहुत महंगा पड़ रहा है। कुछ दिनों में सम्भवतः ईंट मिलेगा ही नहीं और सम्पूर्ण व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों के बन्द हो जाने की सम्भावना है और ईंट का संकट आसन्न है। ईंट उद्योग एक लघु और कुटीर उद्योग है। इस उद्योग को बड़ा उद्योग या फैक्ट्री समझना और फैक्ट्री में लागू होने वाले कानूनों को लागू करना न्यायसंगत नहीं है। इस उद्योग में जो कानून लागू किए जा रहे हैं वे अव्यावहारिक हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ईंट उद्योग की जानकारी रखने वालों की एक समिति तत्काल बनाई जाये और इस उद्योग के प्रतिनिधियों से वार्ता करके शीघ्र समाधान निकाला जावे। जिससे ईंट उद्योग पूर्ववत् चालू हो जावे तथा लाखों लोग बेरोजगार होने से बचें और निर्माण कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो।

(iii) Unsatisfactory working of Communications facilities in Amreli District, Gujarat

SHRI NAVIN NAVANI (Amreli) : Amreli district is a big business centre with poor telecommunication facilities. The present trunk circuits are inadequate to meet the flow of trunk traffic to various important stations like Rajkot, Ahmedabad etc.

According to an official source, the installation of wide band microwave system for Rajkot-Amerli-Bhavanagar route will be completed by December 1983 and is likely to be commissioned by the end of March 1984. Meanwhile, it is necessary to take action for satisfactory working of present trunk circuits.

At present the trunk line remains in non-working condition from 10 A.M. to 6 P.M. Consequently, the trading community face lot of hardship.

With commissioning of wide band microwave station at Amreli by the end of March 1984, there will be a lot of microwave channels available between the important stations. It is, therefore, most important that STD facility is provided between Amreli-Rajkot, Amreli-Bhavnagar, Amreli-Ahmedabad and Amreli-Savarkundle.

Similarly, with the commissioning of wide band and microwave station at Amreli, additional trunk circuits from Amreli to other important stations on microwave route may also be given.

The performance of Dhan-Chalala and Dhari Amreli lines is very poor. As a result, Dhari is frequently cut off from the district town. To eliminate this difficulty, channel carrier system be immediately commissioned between Dhari and Amreli.

(iv) Non-payment of sugareane arrears to cane growers in Eastern U. P.

श्री हरिकेश बहादुर: सभापति जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अनेक चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का पैसा बकाया है जिससे गन्ना किसानों के समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो गए हैं। जब कभी यह बकाया किसानों को दिया भी जाता है तो वह भी सूद के साथ नहीं दिया जाता जो भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियम के विपरीत है। इस प्रकार गन्ना किसान सरकार की उदासीनता के कारण शोषण के शिकार हो गए हैं। किसानों से सरकारी कर्ज की वसूली भी बेरहमी के साथ की जा रही है जबकि किसानों का पैसा मिलों पर पहले से ही बकाया है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि गन्ना किसानों का पैसा शीघ्र भुगतान कराया जाये और उन्हें उस पैसे पर सूद भी दिया जाय तथा जब तक किसानों का पैसा उन्हें मिल न जाये तब तक सरकारी विभागों द्वारा किसानों को दिये गये कर्ज की वसूली तत्काल बन्द कर दी जाय। जो चीनी मिलें, मिल मालिकों की लापरवाही के कारण

किसानों को पैसा न दे सकी है, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना भी अति आवश्यक है।

(v) Industrialisation of Saidpur constituency of Uttar Pradesh.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री का ध्यान संसदीय क्षेत्र सैदपुर की वर्तमान गरीबी और भुखमरी की ओर ले जाना चाहता हूं। यह क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी का ग्रामीण पिछड़ा इलाका है। यहां आठ लाख मतदाता हैं। इनमें पच्चीस प्रतिशत लोग खेती करते हैं। शेष लोग खेतों और मजदूरी पर निर्भर हैं। कृषि योग्य भूमि जनसंख्या की तुलना में यहां कम हैं। इसी कारण 45 प्रतिशत लोग बेकारी तथा असमर्थता की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। 20 प्रतिशत लोग आज एक वक्त खाना खाते हैं। कोई उद्योग यहां नहीं है। जौनपुर जनपद में केराकत और ब्यालमी नामक दो विधान सभायें तीन लाख मतदाताओं से बनी हैं। गोमती और राई नदी इसके बीच से गुजरती हैं। इसके भयानक बाढ़ से लाखों रुपये की फसल बर्बाद प्रतिवर्ष होती है।

मान्यवर, जक्खनियां और सादात गाजीपुर की दो विधान-सभाएं हैं। यदि यहां कोई केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से बड़ा तीन-चार औद्योगिक कारखाना नहीं खोला गया तो स्थिति बड़ी गम्भीर हो जायेगी। यहां कागज, खाद, अल्युमिनियम आदि का कारखाना सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। दुग्ध और खोए के वर्तमान उत्पादन को देखते हुए गुजरात के अमूल जैसा भी कारखाना स्थापित किया जा सकता है। ईंट के भट्टे के साथ ही बुनकरों को सहायता देकर हैंडलूम एवं अन्य इसी प्रकार के लघु उद्योगों को भी यहां विकसित किया जा सकता है।

अतः मैं उद्योग मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे तुरन्त सैदपुर के गरीबों की मुक्ति के लिए यहां के औद्योगिकरण के सम्बन्ध में सक्रिय हों।

(vi) Need for Improving the working conditions of Medical representatives.

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : There are about 20,000 medical respresentatives all over India engaged in the Organised and unorganised Drugs & Pharmaceutical Industry. Their services are terminated without assigning any reasons, They are transferred on whims and fancies of the Management, and without minimum bonus. Normally, a medical representative has to work for 14 to 16 hours daily. But, no over-time is allowed to them. All the companies in this industry should be categorised according to the sales turnover. The fair wages committee has suggested that the minimum wages of an employee should be somewhere between the needbased wage and living wage as envisaged in the Constitution of India. The 15th Labour Conference recommended a formula for the need based wage. While deciding the minimum wages of the sales promotion employees including the medical respresentatives, these two points should be taken into consideration. When the charter of demands submitted in in 1978 by the medical respresentatives failed they agitated. Then, the Government of India constituted in 1980 a National Triparty Committee. There were negotiations in 1982 and a report was submitted to the Government of India. Even after a lapse of about 14 months, the report has not been published and no action taken on it for the betterment of these Medical Representatives. I, therefore, request the Central Government to immediately publish the report and take effective follow up action to implement its recommendations.

(vii) Demands of ticket checking staff of Indian Railways.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Today, the ticket checking staff working in Indian Railways are sitting on 24 hours mass fasting...

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, आज शास्त्री जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य हमको बराबर उपदेश देते रहे हैं कि हिन्दी में बोलो, क्या आज उनके लिए जरूरी हो गया है कि अंग्रेजी में बोलें ? उन्हें तो हिन्दी में बोलना चाहिए।